

## प्रारूप - 30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं)

**FORM - I**  
**(for linear projects)**

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector ..... Dehradun .....No ... Memo 101 ...Dated ... 13/11/17 ...**TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC (pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.13 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of ..... (name of user agency) for U.T.N (purpose for diversion of forest land) in Dehradun district falls within jurisdiction of Kalmi village (s) in Kalmi tehsils.

It is further certified that -

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.13 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights committed (s), Gram Sabha (s) sub-division level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ..... to ..... annexure .....
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl - As above

Signature  
(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी  
देहरादून



**FORM – II**  
**(for projects other than linear projects)**

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector ..... *Dehradun* .....

No ... *Memo 101* ...

Dated ... *13/11/17* ...

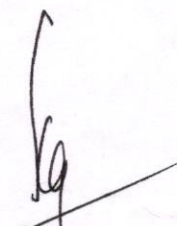
**TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC (pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that *0.13* hectares of forest land proposed to be diverted in favour of ..... (name of user agency) for *U.I.N* (purpose for diversion of forest land) in *Dehradun* district falls within jurisdiction of *Kabli* village (s) in *Kabli* tehsils.

It is further certified that –

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire..... hectares of forest land for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights committed (s), Gram Sabha (s) sub-division level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ..... to ..... annexure .....
- (b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA.
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of *Dehradun* villages (s) is enclosed as annexure ..... to annexure.....
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50 % of the members of Gram Sabha present.
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
- (f) The right of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Eucl – As above

  
 Signature  
 (Full name and official seal of the District Collector)  
*निदेशिका देहरादून*



प्रारूप - 30.1

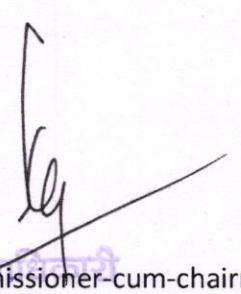
**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER**  
**DISTRICT Dum Dum (U.K)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA) 2006.

A meeting of the district level committee of Dum Dum district, constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss S.A. Murgala I.A.S deputy commissioner Dum Dum on dated 12.1.11 at time 10.30 AM at Dum Dum in which application claiming rights in 0.13 hect area measuring 0.13 hect for the construction of pipeline forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Kelhi sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place Dum Dum  
 Dated .....

  
 Deputy Commissioner-cum-chairman  
 District Level Committee



परियोजना का नाम - एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय एवं गुजर बस्ती पेयजल योजना

कार्यालय उप जिलाधिकारी कालसी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति कालसी

उपखण्ड कालसी परिक्षेत्र के अन्तर्गत एकलव्य आदर्श आवासीय एवं गुजर बस्ती हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.113 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.113 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.113 हे0 वन भूमि) का उत्तराखण्ड पेयजल प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कालसी) की दिनांक 10-11-17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री पुष्पा तिवारी उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री पुष्पा तिवारी उपजिलाधिकारी कालसी अध्यक्ष।
2. श्री विनोद काला उप प्रभागीय वनाधिकारी चकराता सदस्य।
3. श्री सिद्धन्त खोस सहायक समाज कल्याण अधिकारी कालसी सदस्य/सचिव।
4. श्री अरुण सिंह बी0डी0सी0 क्षेत्र पंचायत सचिव कालसी सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया, कि एकलव्य आदर्श आवासीय एवं गुजर बस्ती परियोजना हेतु 0.113 हे0 वन भूमि हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पत्ति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम, 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्पत्ति से उपखण्ड कालसी परिक्षेत्र के अन्तर्गत एकलव्य आदर्श आवासीय एवं गुजर बस्ती परियोजना के निर्माण हेतु 0.113 हे0 वन भूमि पेयजल निगम प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील कालसी  
जनपद देहरादून

प्रतिलिपि- जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

शिवर राजि डाकपत्थर  
वन क्षेत्राधिकारी  
चकराता वन प्रभाग, चकराता



उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील कालसी  
जनपद देहरादून

तहसीलदार  
कालसी  
जिला मजिस्ट्रेट  
देहरादून



## प्रारूप - 30.3

परियोजना का नाम - एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय एवं गुजर बस्ती पेयजल योजना

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम लोखान  
तहसील ओमडी जिला देवरगढ़

## अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देवरगढ़ के अन्तर्गत एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय परियोजना के निर्माण हेतु (0.13 हे० आरक्षित वन भूमि, — हे० सिविल सोयम भूमि — हे०, वन पंचायत भूमि — हे०) अर्थात् कुल 0.13 हे० वन भूमि का पेय जल विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत लोखान द्वारा दिनांक 28-6-17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है, अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया, कि ग्राम लोखान के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि पेय जल निगम प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह०/-  
ग्राम सचिव  
मुहर सहित

ह०/-  
ग्राम प्रधान/सरपंच  
मुहर सहित

